



---

## करज़ई शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान–पाकिस्तान के मध्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों का ऐतिहासिक विश्लेषण

---

लेखक : फकरुदीन खान  
शोधार्थी  
दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र  
राजस्थान विश्वविद्यालय  
जयपुर

---

### प्रस्तावना

अफगानिस्तान–पाकिस्तान के मध्य अनेक समानताएँ होने के बावजूद भी इनके सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध उत्साहजनक नहीं रहे हैं। विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू देश के आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध है। इस सारभूत सम्बन्ध के संदर्भ में सर्वप्रथम, देश को राष्ट्रीय क्षमता का विकास करना होगा, जो मूलतः तीन चीजों–जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन तथा तकनीकी विकास पर निर्भर करती है। इसके पश्चात् संवैधानिक व्यवस्था, सांस्कृतिक स्वरूप एवं आर्थिक या व्यापारिक विकास की विचारधारा के संदर्भ में राष्ट्र की भूमिका तय करनी होती है। इन आन्तरिक तत्त्वों के आधारों के क्रियान्वयन में बाह्य विश्व में आदान–प्रदान करना पड़ता है, जो सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं आर्थिक सम्बन्धों के माध्यम से सम्भव हो सकता है।

शनैः शनैः तालिबान एवं अमेरिकी आक्रमण या हस्तक्षेप जैसी विकराल संकट के दौरान सन् 2001 में अफगानिस्तान की शासन–सत्ता में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयनित करज़ई शासन का उदय हुआ। इस कठिन समय में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में हामिद करज़ई का चयन हुआ। जिनके द्वारा अफगानिस्तान के इतिहास में पड़ोसी पाकिस्तान राष्ट्र से अभूतपूर्व आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुए। करज़ई शासनकाल के दौरान न केवल अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुयी वरन् अफगानिस्तान–पाकिस्तान की मध्य आपसी संस्कृति को भी एक नवीन आयाम प्राप्त हुआ।



## भूमिका:

अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य करज़ई प्रयासों के फलस्वरूप कई समझौते, संधि और यात्राएं सम्पन्न हुयी जिनके माध्यम से दोनों देशों के सम्बन्ध में सुगमता आ सकी। बाहरी और आन्तरिक रूप आहत अफगानिस्तान आर्थिक विकास के मामले में बहुत कुछ खो चुका था, उससे उबरने की कोशिश का मूर्त रूप हामिद करज़ई शासनकाल में आया। वर्ष 2008–09 में जीडीपी वृद्धि की दर उच्च रही एवं 2008–09 में अर्थव्यवस्था में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगले वर्ष में यह घटकर 8.4 प्रतिशत हो गई, और 2011–12 में और धीमी हो गई, विश्व बैंक ने 2012 में विकास दर को 11.8 प्रतिशत करने की उम्मीद की। हालांकि, ये प्रभावशाली दरें टिकाऊ नहीं रही। दिसंबर 2001 में अमेरिकियों के देश में चले जाने के बाद लम्बे समय से चली आ रही तबाही और प्रचुर मात्रा में बाहरी सहायता के कारण कुछ सुधार का प्रतिनिधित्व हुआ। डोनर अनुदान राष्ट्रीय आय का 10 से 16 प्रतिशत के बीच रहा। दिसम्बर 2014 तक अमेरिकी और नाटो सैनिकों की छुट्टी के बाद इनमें काफी गिरावट आयी।

2012–13 में, नाममात्र जीडीपी (अफीम को छोड़कर) यूएस + 19.8 बिलियन का अनुमान लगाया गया था, जो कि 33.4 मिलियन की आबादी के लिए, प्रति व्यक्ति केवल यूएस + 595 तक काम करता था। जबकि देश में 2.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि आयात खरीदने में यूएस + 11.17 बिलियन का खर्च आया। इसने लगभग US + 8.6 बिलियन या GDP का लगभग 43.1 प्रतिशत व्यापार असंतुलन छोड़ दिया। यह दाताओं द्वारा वित्तपोषित किया गया था, ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका में। जैसा कि अग्रवर्णित तालिका में दिखाया गया है, 2010–11 में अकेले पाकिस्तान के साथ व्यापार घाटा लगभग यूएस + 2.2 बिलियन या कुल का लगभग 26 प्रतिशत था। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के देश से प्रस्थान के बाद देश में विदेशी सहायता के प्रवाह पर एक निचोड़ के साथ, यह अफगानिस्तान– पाकिस्तान व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला था।

हामिद करज़ई शासन काल के दौरान अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 50 से अधिक देशों ने अरबों डॉलर की सहायता प्रदान की है। जिसकी वजह से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत कर्ज देश में बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख रीढ़ की हड्डी के रूप में परिवहन प्रणाली और कृषि उत्पादन को जाना जाता है। “देश में अनार, खुबानी, खरबूजे, ताजा–मेवा और अन्य फल प्रमुख रूप से निर्यात किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख



भूमिका निभाते हैं।" कृषि क्षेत्र में इस उत्पादन का 11 प्रतिशत भाग खेती और कृषि कार्यों की उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से जुड़ा है।

देश के चालू खाता काफी हद तक वित्त पोषण बाहरी सहायता पर निर्भर है। विभिन्न परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बजट तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय अफगानिस्तान राजस्व संग्रह और सार्वजनिक व्यय सुधार पर ध्यान केन्द्रित करता रहा। देश में बढ़ते राजस्व का घाटा और बेरोजगारी ने आम जनता के जीवन निर्वाह में कठिनाई होती है।

करज़ई शासन काल में निरन्तर आर्थिक सुधार के लिए ऊर्जा, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, कौशल, रोजगार, धन, कारोबार, निर्माण, उद्योग, परिवहन की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस हेतु अफगानिस्तान में बैंकों को खोलने के लिए केन्द्रिय बैंक ऑफ अफगानिस्तान ने मदद की। 2003 के बाद से 16 नये बैंक अफगानिस्तान इंटरनेशनल बैंक, काबुल बैंक, अजीजी बैंक, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक और माइकोफाइनेंस बैंक की स्थापना की गई।

हामिद करज़ई शासन के दौरान अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों काबुल, कंधार, जलालबाद, हेरात और मजार-ए-शरीफ में भारी व बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए छोटी कम्पनी, छोटे कल कारखाने, लघु उद्योग को भी प्राथमिकता के साथ खोला जा रहा है। "दूरसंचार में निवेश से 1,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अफगान में कालीन बनाने का व्यापार फिर से लोकप्रिय व विकसित हो रहा है।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के आर्थिक सम्बन्धों की स्थिति मादक पदार्थों, अफीम, हथियार और तस्करी के कारण और भी खराब हो रही थी। एक ओर तो देश में चरमपंथी तालिबान आतंकी गतिविधियों में लिप्त था, जो देश को आर्थिक, राजनैतिक नुकसान पहुंचाते रहते थे एवं देश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा कर रहे थे। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से सरकारी तंत्र, शिक्षा, मानव अधिकार, स्त्री उपेक्षा को बढ़ावा मिला था। यूएनओडीसी के सूरी फेडोटोन का कहना था कि अफगानिस्तान के 34 में से 15 प्रांतों में अफीम की खेती हो रही थी।

1999 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 1997 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तस्करी के जरिए होने वाला व्यापार 2.5 बिलियन डॉलर (102 अरब रुपये) के बराबर था, जो अफगानिस्तान के कुल सकल घरेलू उत्पाद का आधार बैठता है।" इस बात से स्पष्ट पता चलता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राजनयिक सम्बन्ध कैसे भी हों,



व्यापार के दृष्टिकोण से दोनों देश समान विचारधारा रखते हैं। इन दोनों देशों के मध्य जारी गतिरोध को दूर करने के लिए अमेरिका विदेश मंत्री द्वारा दोनों देशों के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) अफगानिस्तान–पाकिस्तान ट्रांजिस्ट व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अन्तर्गत दोनों देशों के मध्य संचार सुगमता लाने का प्रयास किया गया।

जुलाई 2012 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एपीटीटीए बढ़ाने पर तजाकिस्तान भी सहमत हो गया है, जिससे उत्तर–दक्षिण की दिशा में व्यापार बढ़ने की सम्भावना है। प्रस्तावित समझौते में तजाकिस्तान अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान और पाकिस्तान समझौते में तजाकिस्तान अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आयात–निर्यात करने की सुविधाएँ प्रदान करेगा। एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कि इस समझौते से दोनों देशों के मध्य करीब 5 अरब डॉलर तक व्यापार पहुँचने की सम्भावना थी, वर्ल्ड बैंक ने 2012 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो सकती है।

APTTA पाकिस्तान और अफगानिस्तान द्वारा 2010 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यह समझौता दो देशों के बीच माल की आवाजाही को काफी हद तक सुगम बनाने के लिए किया गया है।

तापी गैस परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है। तापी शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के आदि अक्षरों से मिलकर बना है। यह तापी शब्द उक्त चारों देशों को एक साथ व्यक्त करता है। त=तुर्कमेनिस्तान, अ=अफगानिस्तान, प=पाकिस्तान और इ=इंडिया। तापी उक्त देशों का संक्षिप्त रूप है। यह परियोजना तुर्कमेनिस्तान से प्रारम्भ होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक जाएगी।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.5 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 7 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवां सदस्य बन गया। पाकिस्तान ने शुरू में अफगानिस्तान की दक्षेस में सदस्यता का विरोध किया था लेकिन अन्ततः भारत के समर्थन से अफगानिस्तान को सार्क में एक सदस्य के रूप में करज़ई कार्यकाल में मान्यता मिली।



आधुनिकीकरण के साथ, ऊर्जा सुरक्षा हमेशा दुनिया के सभी देशों के लिए चिंता का विषय रही है। ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और ऊर्जा के उपयोग पर लोगों का जीवन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर हो रही है, इसलिए एक सुरक्षित भविष्य को बनाए रखने के लिए ऊर्जा उत्पादन-खपत में व्यवस्थित होने की आवश्यकता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र, पूरी दुनिया में विशाल जनसंख्या आधार के साथ, इस दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से चिह्नित तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था व प्रगति के लिए इस क्षेत्र के उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) का गठन किया गया था। दक्षिण एशिया में निकटवर्ती देश होने के कारण अफगानिस्तान-पाकिस्तान ने एकमत होकर समझा कि ऊर्जा खपत बिना किसी राष्ट्र का विकास लगभग असंभव है। अतएव अफगानिस्तान –पाकिस्तान को इस सम्बन्ध आपसी सहयोग एवं सद्भाव नीति की आवश्यकता है। करज़ई शासन के दौरान अफगानिस्तान में उक्त संगठन के प्रति ऐतिहासिक प्रयास किए गए, जिनके परिणामस्वरूप न केवल वह इस संगठन से जुड़े वरन् अफगान के लिए ऊर्जा प्राप्ति केन्द्र में कारक बन सके। इसके अतिरिक्त करज़ई के प्रयासों के फलस्वरूप पड़ोसी पाकिस्तान के जटिल सम्बन्धों में थोड़ी बहुत सुगमता आ सकी।

अफगानिस्तान की परम्परागत विदेश नीति के अन्तर्गत गुटनिरपेक्षता द्वारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, मित्रता व सभी देशों के साथ सहयोग है। पश्तूनिस्तान माँग का समर्थन अफगानिस्तान-पाकिस्तान विदेश नीति का मुख्य तत्त्व है। अफगानिस्तान ने प्रारम्भ से ही अपने वैदेशिक सम्बन्धों में उल्लेखनीय गत्यात्मक पहल और व्यावहारिक का परिचय दिया। उसने सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा, पृथकतावाद का विरोध और अपनी शक्ति के प्रति सजगता आदि गुणों को विदेश नीति में शामिल किया, साथ ही हर स्थिति में अपनी स्वतन्त्रता का समर्थन किया है। अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का समर्थन कर उपनिवेशवाद, जातिवाद, सैनिक सन्धियों व शस्त्रहोड़ का विरोध करता है।<sup>27</sup> वह अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, शान्तिपूर्ण सम्बन्धों में विश्वास तथा निरस्त्रीकरण का समर्थन कर विश्व में किसी भी प्रकार के युद्ध का विरोध करता है।

अफगानिस्तान के अन्य देशों से सांस्कृतिक सम्बन्धों के इन आयामों को राष्ट्रपति दाउद, तराकी, अमीन, कारमल एवं नजीबुल्ला आदि सभी ने समय व स्थिति के बदलते क्रम के तहत स्वीकार किया। इस प्रकार अफगानिस्तान का आधार-संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र



का अनुसरण, मानवीय अधिकारों की घोषणा का सम्मान, आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन, सम्पूर्ण विश्व में हर प्रकार के उपनिवेशवाद का अन्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि है। वह बल प्रयोग का सहारा लिए बिना विवादों की समाप्ति के द्वारा विश्व शान्ति की रक्षा का लक्ष्य रखता है।

अफगानिस्तान—पाकिस्तान की संस्कृति को गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि यह एक बहुभाषी, खानाबदोश, आदिवासी समाज, विभिन्न परम्पराओं, संस्कृति को मानने वाले दोनो देश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पश्तून संस्कृति यहाँ सबसे ज्यादा विकसित है। यहाँ फारसी, तुर्की संस्कृति को मानने वाले भी मिलते हैं। अफगानिस्तानी—पाकिस्तानी अपनी संस्कृति, धर्म, वंश, परम्परा, राष्ट्रीयता का बड़े कड़े ढंग से पालन करते हैं। उनके लिए ये सब अनिवार्य आवश्यक है।

### अध्ययन का उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य करजई शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान—पाकिस्तान के मध्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध का ऐतिहासिक विश्लेषण है।

इस विषय पर यद्यपि बिखरी हुई साम्रगी पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है परन्तु एक ही स्थान पर इकट्ठी साम्रगी का अभाव है क्योंकि इस विषय पर अभी आवश्यक और पूर्णरूपेण शोध कार्य नहीं हुआ है। इस दृष्टि से यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यद्यपि इस अध्ययन में त्रुटियाँ हो सकती हैं परन्तु फिर भी मैंने इस विषय पर अधिकाधिक गहन और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

### शोध प्रविधि:

ऐतिहासिक घटना या व्यक्ति के विषय में जो कुछ तथ्य प्रदान करते हैं, उनकी आवृत्ति उन साधनों के अन्तर्गत प्रत्यक्षतः समाहित नहीं रहती। एक व्यक्ति जो ऐतिहासिक तथ्य के विषय में तात्कालिक घटना से सम्बन्धित व्यक्ति के मुंह से सुने—सुनाये वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, ऐसे वर्णन को द्वितीयक साधन कहते हैं। इनमें यद्यपि सत्य का अंश रहता



है किन्तु प्रथम साक्षी से द्वितीय स्रोतों तक पहुँचते-पहुँचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन आ जाता है जिससे उसके दोष-युक्त होने की सम्भावना रहती है। दार्शनिक विधि के अन्तर्गत अध्ययन हेतु चुने गये मुद्दे को ही प्रारम्भिक बिन्दु माना जाता है। इसमें जिन बातों पर बल दिया जाता है उनमें मुख्यतः किसी व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र या समूह के चिन्तन में किसी दिये समय पर पाये जाने वाले विचारों की व्यवस्था या प्रभावी धारणाओं या विचारों का विश्लेषण तथा यह प्रदर्शित करना कि वे उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों, व्यवहारों तथा साहित्य में किस प्रकार प्रतिबिम्बित है या किसी महान चिन्तक या समूह विशेष के व्यक्तियों के ऐसे विचारों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना जो उनके व्यक्तिगत अभिवृत्तियों एवं चर्चाओं, जीवन एवं उपलब्धियों में प्रदर्शित होते हैं।

### निष्कर्ष:

अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों के मध्य एक नवीन ऊर्जा का संचार वर्ष 2001 से हामिद करजई के राष्ट्रपति शासनकाल के साथ हुआ। करजई शासनकाल अन्तर्गत अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति हेतु कई समझौते, संधि, यात्राएं एवं उद्घोषणा हुयी, जिससे दोनों देशों के सम्बन्ध में सरलता व सुगमता व्याप्त हो सकी।

करजई शासनकाल के प्रारम्भ में एवं इससे पूर्व में अफगानिस्तान आन्तरिक रूप आहत हो, आर्थिक विकास के मार्ग से दूर हो गया था। इस समय उसे सर्वाधिक आवश्यकता थी अपने पड़ोसी देशों से भरपूर सहायता की, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु करजई ने भारत एवं पाकिस्तान से अफगानिस्तान की आर्थिक सुदृढता हेतु अनेक प्रयास किए। वर्ष 2001 के पश्चात् से ही पड़ोसी देश अफगानिस्तान की भारत ने अभूतपूर्व मदद की। जबकि अफगानिस्तान के सबसे निकटवर्ती पड़ोसी देश होने के साथ जो नैतिक जिम्मेदारी पाकिस्तान की रहीं, वह उस सहयोग को जिम्मेदारीपूर्वक निभाने में सफल नहीं हो सका।

इसी क्रम में अफगानिस्तान-पाकिस्तान के मध्य वर्ष 2010 में, पारगमन व्यापार समझौते (APTTA) के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन किया गया। जिसके अन्तर्गत दोनों देशों ने पाकिस्तान रेलवे (पीआर), से जुड़ने के लिए अफगानिस्तान में रेल पटरियों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो कि कम से कम





2005 से चल रहा था। इस समझौते के जरिए दोनों देश अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति में प्रगढ़ता लाने के लिए एकमत हुए।

करज़ई शासनकाल के दौरान ही अफगानिस्तान पाकिस्तान पीपुल्स फ्रेंडशिप एसोसिएशन एक गैर-सरकारी संगठन समूह का निर्माण सम्भव हुआ जिसका उद्देश्य शरणार्थियों को सहायता देना, मुक्त व्यापार क्षेत्र, शिक्षा, भूमि और गरीबी, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों को चुनौती देना इत्यादि को सम्मिलित किया गया।

वस्तुतः आर्थिक दृष्टि से अफगानिस्तान एक अविकसित कृषि प्रधान देश रहा है। अफगानिस्तान का अधिकांश भाग पर्वतीय एवं शुष्क होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। किन्तु फिर भी यहाँ कृषि एवं पशुपालन का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। यहाँ के मैदानों एवं अनेक उर्वर घाटियों में नहरों आदि द्वारा सिंचाई करके फल, सब्जियाँ उपजाए जाते हैं। जिनके जरिए पड़ोसी देशों से सुगम आयात-निर्यात व्यवस्था कायम कर आर्थिक मजबूती प्राप्त की जा सके।

अफगानिस्तान में शांति व युद्ध प्रक्रिया के संबंध में अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच बढ़ते मतभेद, तूख्रम में सीमावर्ती तनाव और बढ़ते पारस्परिक अविश्वास के कारण दोनों पड़ोसी देशों की राजनैतिक चुनौतियों का उनके आर्थिक संबंधों पर भी नकारात्मक असर पड़ा। करज़ई के लोकतांत्रिक शासनकाल में पाकिस्तान सरकार की अफगानिस्तान के संबंध में नीति स्पष्ट नहीं थी जिसका स्पष्ट असर आर्थिक सम्बन्धों में देखने को मिला। अफगानिस्तान-पाकिस्तान के आर्थिक सम्बन्धों की स्थिति मादक पदार्थों, अफीम, हथियार और तस्करी के कारण और भी खराब हो रही थी। एक ओर तो देश में चरमपंथी तालिबान आतंकी गतिविधियों में लिप्त था, जो देश को आर्थिक, राजनैतिक नुकसान पहुंचाते रहते थे एवं देश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा कर रहे थे। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से सरकारी तंत्र, शिक्षा, मानव अधिकार, स्त्री उपेक्षा को बढ़ावा मिला था।

यद्यपि अफगानिस्तान में खनिज भण्डार अपार मात्रा में उपलब्ध रहे हैं, किन्तु अफगान के पास इन प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करने के लिए साधन नहीं हैं। इसलिए अफगान सीमावर्ती राष्ट्र पाकिस्तान से इस संदर्भ में सहायता की आशा रखता है जिससे अफगानिस्तान-पाकिस्तान का समुचित विकास हो सकें। किन्तु इस परिप्रेक्ष्य में सफलता मिलने के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान की पूर्ण सहायता की आवश्यकता है जोंकि अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण सम्भव नहीं हो पाती है।





इसी श्रंखलाबद्ध स्वरूप में अफगानिस्तान–पाकिस्तान के सांस्कृतिक सम्बन्धों में करज़ई के राष्ट्रपति कार्यकाल में नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। वर्ष 2001 के पश्चात् से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य आपसी संस्कृति का आदान–प्रदान में प्रगढ़ता आने लगी, जिसका अधिक श्रेय करज़ई के पाकिस्तान से होने वाले खेल, मनोरंजन, वेश–भूषा, भाषा इत्यादि में हुए समझौते, यात्राएँ एवं सकारात्मक प्रयासों को जाता है।

अफगानिस्तान–पाकिस्तान के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्धों की दृढ़ता में एक कदम वर्ष 2010 में दोनों देशों के अन्तर्गत हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता [चज्ज] द्वारा साकार हो पाया, जिसका उद्देश्य दो देशों के बीच माल की आवाजाही को काफी हद तक सुगम बनाना था। यदि अफगानिस्तान–पाकिस्तान की संस्कृति को गौर से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि यह एक बहुभाषी, खानाबदोश, आदिवासी समाज, विभिन्न परम्पराओं, संस्कृति को मानने वाले दोनो देश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अफगानिस्तानी–पाकिस्तानी अपनी संस्कृति, धर्म, वंश, परम्परा, राष्ट्रीयता का बड़े कड़े ढंग से पालन करते हैं। उनके लिए ये सब अनिवार्य आवश्यक है। दोनों देशों की इस सांस्कृतिक धरोहरों को ओर अधिक मजबूत करने का कार्य करज़ई कार्यकाल में बखूबी निभाया गया। करज़ई शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान में 'रावा'–रिवोलयूशनरी एसोसिएशन ऑफ अफगानिस्तान बीमेन, महिलाओं की एकमात्र संस्था का अधिक दृढ़तापूर्ण संचालन किया जाने लगा। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पाकिस्तान की महिलाओं पर भी पड़ा एवं पाकिस्तानी महिलाएं इससे प्रेरित हो अधिक सजग बन सकी। उपरोक्त तथ्यों द्वारा निष्कर्ष रूप से यह कहना उचित होगा, कि अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध ऐतिहासिक रूप से समरूप रहे हैं, जिनकों अधिक सुनियोजित व सुदृढ़ मार्ग पर ले जाने का श्रेय अफगानिस्तानी नेता हामिद करज़ई को जाता है, जिन्होंने वर्ष 2001 से वर्ष 2014 के अपने सम्पूर्ण राष्ट्रपति कार्यकाल में न केवल अफगानिस्तानी संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया वरन् सीमावर्ती पड़ोसी देश पाकिस्तान की संस्कृति का समानरूप से सम्मान किया है।

अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि अफगानिस्तान–पाकिस्तान सन् 2001–14, करज़ई शासन के दौरान पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के आर्थिक सम्बन्धों को बल मिला है। करज़ई शासन के प्रयासों के कारण ही अफगानिस्तान–पाकिस्तान के आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ता मिली जिसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति एवं कुल राष्ट्रीय आय में करिश्माई वृद्धि अंकित की गई।



---

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. फहद हुमायूँ, "पाकिस्तान में करज़ई : महान उम्मीदों को पूरा करना", 28, अगस्त 2013, जिन्ना इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद ।
2. दीज डेटा आर द वर्ल्ड बैंक, *अफगानिस्तान इकोनॉमिक अपडेट*, अप्रैल 2013–14 ।
3. डॉन के संपादकीय, "अनारक्षित मुद्दे : अफगान राष्ट्रपति की यात्रा" 28, अगस्त 2013, पृष्ठ 7 ।
4. विलियम डेलरिम्पल, "रिटर्न ऑफ ए किंग : द बैटल फॉर अफगानिस्तान", न्यूयॉर्क, नोपक, 2013, पी, 76 ।
5. द इकोनॉमिस्ट, "अफगानिस्तान से वापसी : बड़ा प्रतिगामी", अप्रैल, 2013, पी. 34 ।
6. उपाध्याय, अर्चना, 'भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध', 2005, संजय प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 46–59 ।
7. खंडेला, मानचंद्र, *अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद: एक परिचय*, 2002, अविष्कार पब्लिशर्स, जोधपुर, पृ.स. 58–71 ।
8. राजकिशोर मुस्लिम आंतकवाद बनाम अमेरिका, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 12–14 ।
9. काउंटर नारकोटिक्स मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट मार्च 28, 2014 ।
10. आईआरआईएन अफगानिस्तान खाद्य अभी भी लाखों के लए असहनीय 11 अक्टूबर 2010 ।
11. तोबिया जी, जे. निर्यातक अफगानिस्तान इंटरनेट से संग्रहित 17 नवम्बर 2009 ।